

प्रेषक,

अ० रणवीर सिंह,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,

राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 26 अक्टूबर, 2007.

विषय: उपभोक्ता संरक्षण एकीकृत परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के जिला फोरमों के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, निदेशक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 4(2)2005-सीपीयू(पीटी) XIX दिनांक 30 मार्च, 2007 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रदेश के 13 जनपदों में क्रियाशील जिला उपभोक्ता फोरमों के सुदृढीकरण हेतु प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹0 1,43,04,000.00 (रुपये एक करोड़, तैंतालिस लाख, चार हजार मात्र) की धनराशि अनुदान के रूप में अवमुक्त की गई है। उक्त धनराशि में से तैरह जनपदों में स्थापित जिला उपभोक्ता फोरा में नॉन-बिल्डिंग एसेट्स स्थापित किये जाने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कुल ₹0 55.54 लाख (रुपये पचपन लाख, चौवन हजार मात्र) के उपभोग हेतु आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र के साथ संलग्नक -1, में अंकित विवरणानुसार प्रत्येक जनपद के सम्मुख अंकित किये गये प्रयोजनों, अर्थात् (क) कोर्ट रूम फर्नीचर (ख) अन्य फर्नीचर (ग) कार्यालय उपकरण (घ) सेट ऑफ रिफरेंस बुक्स (ङ) कम्प्यूटर पेरिफेरल्स प्रति जनपद के सम्मुख अंकित दरों के अनुसार व्यय की जायेगी तथा धनराशि का व्यय संलग्नक -2 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश/मापदण्ड के अनुरूप ही खर्च किया जायेगा।

2. उक्त समस्त उपकरण डी.जी.एस एण्ड डी. की निर्धारित दरों के अनुरूप ही क्रय किये जायेंगे तथा क्रय की गयी सामग्री के व्यय विवरण तथा भारत सरकार के पत्र सं0 4(2)/2005-सी.पी.यू (पी.टी.) दिनांक 22.08.07 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार धनराशि का उपयोग किया जायेगा तथा उक्त पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र फॉर्म जी. एफ.आर. 19ए के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

3. वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुरितका, बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज रुल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

5. यह सूचित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया गया है। जिसके लिये वित्तीय हस्तपुरितका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम

अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली गयी है।

6. भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग नान बिल्डिंग एसेट्स के लिए 06 माह के भीतर किया जाना आवश्यक है तथा समय से उपयोग किये जाने के लिये यह सुनिश्चित करें कि धनराशि को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय, तथा व्यय का विवरण यथासमय प्रत्येक माह बीएम-13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

7. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"3456- सिविल पूर्ति-001-निर्देशन तथा प्रशासन-आयोजनागत-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0105- राज्य आयोग एवं जिला फोरमों की स्थापना -20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-973/वि0अनु0-5/2007 दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक:उपर्युक्त।

भवदीय,
/ (रणवीर सिंह)
सचिव।

संख्या 259 (1)/ 07-XIX-2/36 खाद्य/2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओवरसय भवन, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 4(2)2005-सीपीयू(पीटी) XIX दिनांक 30 मार्च, 2007 के संदर्भ में।
3. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देहरादून।
4. समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तराखण्ड।
5. निबन्धक, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी, खाद्य गढ़वाल/कुमायूँ संभाग, देहरादून/ हल्द्वानी।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग-5/खाद्य अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
10. सुमन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

XSL

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव